

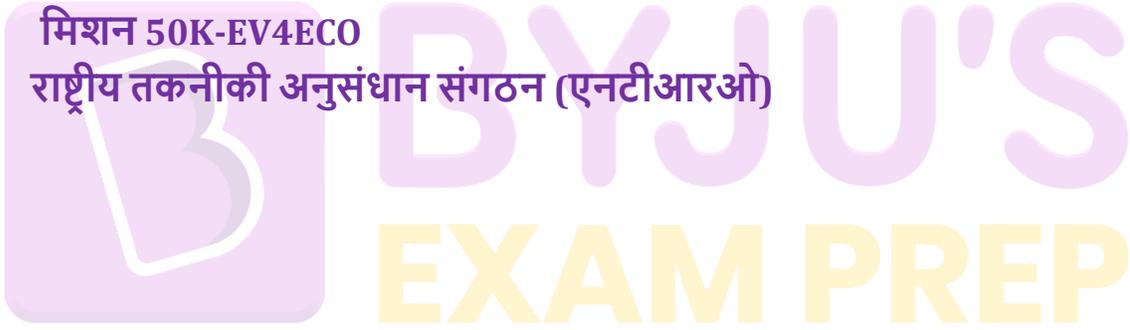
Daily Current Affairs

21 April 2023



Index

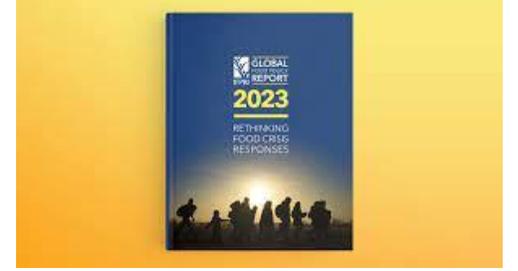
- वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023
- एक्सोबायोलॉजी एक्सपैसिव लाइफ सर्वेयर (ईईएलएस)
- एआईआईबी अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा
- एनएचएआई 2025 तक भारत में 10,000 किलोमीटर 'डिजिटल राजमार्ग' विकसित करेगा
- जल निकायों की पहली जनगणना
- गर्भ-इनी कार्यक्रम
- मिशन 50K-EV4ECO
- राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ)



Important News: International

1. वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023

चर्चा में क्यों:-अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) ने 13 अप्रैल को वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट, 2023 जारी की, जिसमें हितधारकों से लचीला और न्यायसंगत खाद्य प्रणालियों के निर्माण के लिए दीर्घकालिक समाधानों में निवेश करने का आग्रह किया गया।



A.कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं, नागरिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता जैसे कई संकटों के कारण 2020-2022 के दौरान दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा में वृद्धि हुई है।

B.आईएफपीआरआई की रिपोर्ट तीन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देती है: संकट की भविष्यवाणी और तैयारी;

संकट से पहले और दौरान लचीलापन का निर्माण;

और कमजोर समूहों के लिए संकट प्रतिक्रिया को सहायक और समावेशी बनाना।

C.आईएफपीआरआई की रिपोर्ट से पता चलता है कि 45 देशों में 205 मिलियन लोगों ने 2022 में संकट-स्तर की तीव्र खाद्य असुरक्षा या उससे भी बदतर का अनुभव किया। रिपोर्ट संकट के दौरान आजीविका और खाद्य सुरक्षा का समर्थन करने के लिए कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने की वकालत करती है।

D.1975 में स्थापित, आईएफपीआरआई विकासशील देशों में गरीबी को स्थायी रूप से कम करने और भूख और कुपोषण को समाप्त करने के लिए अनुसंधान-आधारित नीति समाधान प्रदान करता है।

E.आईएफपीआरआई का दृष्टिकोण भूख और कुपोषण से मुक्त दुनिया है। यह पांच रणनीतिक अनुसंधान क्षेत्रों पर केंद्रित है:

जलवायु-लचीला और टिकाऊ खाद्य आपूर्ति को बढ़ावा देना।

सभी के लिए स्वस्थ आहार और पोषण को बढ़ावा देना।

समावेशी और कुशल बाजारों, व्यापार प्रणालियों और खाद्य उद्योग का निर्माण।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बदलना।

संस्थानों और शासन को मजबूत करना।

(SOURCE - LIVEMINT)



2. एक्सोबायोलॉजी एक्सपैंसिव लाइफ सर्वेयर (ईईएलएस)

चर्चा में क्यों:- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक सांप जैसा रोबोट विकसित कर रहा है जिसे एक्सोबायोलॉजी एक्सोबायोलॉजी एक्सिलेंट लाइफ सर्वेयर (ईईएलएस) के रूप में जाना जाता है, जो विभिन्न इलाकों में अपनी विविध अनुकूलन क्षमता के माध्यम से अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा दे सकता है।



A. एक मोबाइल डिवाइस प्लेटफॉर्म है जिसकी कल्पना आंतरिक संरचना संरचनाओं का पता लगाने, रहने की क्षमता का आकलन करने और अंततः जीवन के सबूत की खोज करने के लिए की गई है।

B. को समुद्र-दुनिया से प्रेरित इलाके, तरलीकृत मीडिया, संलग्न भूलभुलैया वातावरण और ट्रैवर्सिंग तरल पदार्थों के अनुकूल होने के लिए डिज़ाइन किया गया है

C. सांप जैसा रोबोट है जो उबड़-खाबड़ इलाके से गुजर सकता है।

D. इसका उद्देश्य शनि के चंद्रमा की सतह की जांच करना और यह निर्धारित करना है कि क्या जीवन मौजूद है। ईईएलएस अपनी तरह की पहली घूर्णन प्रणोदन इकाइयों का उपयोग करता है जो पानी के नीचे की पटरियों, मनोरंजक तंत्र और प्रोपेलर इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं, जिससे रोबोट को एक प्लम वेंट निकास तक पहुंचने और इसे अपने महासागर स्रोत तक ले जाने की अनुमति मिलती है।

E. कई, समान, खंडों से बना है जिसमें एक्ट्यूएशन और प्रणोदन तंत्र दोनों शामिल हैं और साथ ही उन्हें चलाने के लिए शक्ति और संचार इलेक्ट्रॉनिक्स भी शामिल हैं।

(SOURCE - INDIAN EXPRESS)

3. एआईआईबी अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा

चर्चा में क्यों:- एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) ने हाल ही में अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में अपना पहला अंतरिम परिचालन केंद्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एक विदेश कार्यालय स्थापित करने में अपने प्रारंभिक प्रवेश को चिह्नित करता है। एआईआईबी अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा



A. AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो स्थिरता को प्राथमिकता देने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण पर केंद्रित है। इस साल के अंत में COP28 के लिए मेजबान देश



Daily Current Affairs

के रूप में, संयुक्त अरब अमीरात ने जलवायु वित्त के महत्व पर जोर दिया है, जो राष्ट्रों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है क्योंकि वे जलवायु कार्रवाई के प्रति अपने प्रयासों और प्रतिबद्धताओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं।

B.एआईआईबी ने अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में अपना पहला अंतरिम संचालन केंद्र स्थापित किया है, जो इसके प्रारंभिक विदेशी कार्यालय के रूप में काम करेगा।

C.कार्यालय का मध्य पूर्व और दुनिया में एक रणनीतिक स्थान होगा, और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण द्वारा बैंक के विकास एजेंडे का समर्थन करेगा जो स्थायी आर्थिक विकास को प्राथमिकता देते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

D.एआईआईबी एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसे 2016 में एशिया और उससे परे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया था।

E.बैंक का मुख्यालय बीजिंग, चीन में है, और इसमें 100 से अधिक सदस्य देश हैं, जिनमें यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसी कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।

F.एआईआईबी का मिशन सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, धन उत्पन्न करना और बुनियादी ढांचे और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश करके एशिया में बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी में सुधार करना है।

(SOURCE – ECONOMIC TIMES)



Important News: National

4. एनएचएआई 2025 तक भारत में 10,000 किलोमीटर 'डिजिटल राजमार्ग' विकसित करेगा

चर्चा में क्यों:- सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) वित्त वर्ष 2024-25 तक देश भर में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल (ओएफसी) बुनियादी ढांचे को विकसित करने की दिशा में काम कर रही है।



A. राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल), एनएचएआई का पूर्ण स्वामित्व वाला विशेष प्रयोजन वाहन, ओएफसी बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ एकीकृत उपयोगिता गलियारों को विकसित करके "डिजिटल राजमार्गों" के नेटवर्क को लागू करेगा।

B. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगभग 1,367 किमी और हैदराबाद-बैंगलोर कॉरिडोर पर 512 किमी को डिजिटल राजमार्ग विकास के लिए पायलट मार्गों के रूप में पहचाना गया है

C. देश भर के दूरदराज के स्थानों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने से ओएफसी नेटवर्क 5 जी और 6 जी जैसी नए युग की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के रोल-आउट में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

D. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली-दौसा-लालसोट खंड में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए उपयोग किया जाने वाला तीन मीटर समर्पित उपयोगिता गलियारा है, जो इस क्षेत्र में 5 जी नेटवर्क के रोल-आउट के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करेगा।

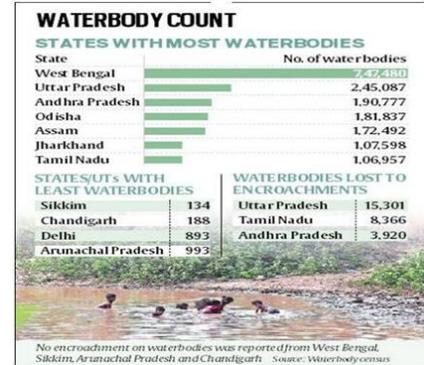
E. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की स्थापना एनएचएआई अधिनियम, 1988 के तहत की गई थी। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। **(SOURCE -NEWS ON AIR)**



5. जल निकायों की पहली जनगणना

चर्चा में क्यों:- में क्यों: जल निकायों की जनगणना में सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में बंगाल सबसे ऊपर है

A.केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित योजना - "सिंचाई जनगणना" के तहत छठी लघु सिंचाई जनगणना (संदर्भ वर्ष 2017-18) के साथ अभिसरण में जल निकायों की पहली जनगणना शुरू की है।



B.जनगणना का उद्देश्य सभी जल निकायों के आकार, स्थिति, अतिक्रमण की स्थिति, उपयोग, भंडारण क्षमता आदि सहित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी एकत्र करके उनके लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करना है।

C. जनगणना एक जल निकाय को सभी प्राकृतिक या मानव निर्मित इकाइयों के रूप में परिभाषित करती है जो सभी तरफ से बंधी होती हैं, जिनके लिए पानी के भंडारण के लिए कुछ या कोई चिनाई का काम नहीं किया जाता है अन्य उद्देश्य (उदाहरण के लिए औद्योगिक, मछली पालन, घरेलू / पीने, मनोरंजन, धार्मिक, भूजल रिचार्ज, आदि)।

D.59.5% जल निकाय तालाब हैं, इसके बाद टैंक, जलाशय, जल संरक्षण योजनाएं / अंतःस्त्रवण टैंक / चेक डैम, झीलें और अन्य हैं।

देश में गणना किए गए 24,24,540 जल निकायों में से 97.1% (23,55,055) ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और केवल 2.9% (69,485) शहरी क्षेत्रों में हैं।

E.पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक (7.47 लाख) और सिक्किम में सबसे कम (134) जल निकाय हैं।

(SOURCE - ECONOMIC TIMES)



6. गर्भ-इनी कार्यक्रम

चर्चा में क्यों :- गर्भ-इनी मई 2015 में गुरुग्राम, हरियाणा, भारत के सिविल अस्पताल में शुरू की गई गर्भवती महिलाओं का एक समूह अध्ययन है। महिलाओं को गर्भावस्था के 20 सप्ताह के भीतर नामांकित किया जाता है और प्रसव तक और प्रसवोत्तर होने तक उनका पालन किया जाता है।

A. गर्भ-इनी (जन्म परिणामों पर उन्नत अनुसंधान के लिए अंतःविषय समूह- डीबीटी इंडिया इनिशिएटिव) को जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा 2014 में एक सहयोगी अंतःविषय कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का नेतृत्व ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (टीएचएसटीआई), एनसीआर बायोटेक क्लस्टर, फरीदाबाद द्वारा किया जाता है।

B. जिसका उद्देश्य (i) प्रतिकूल गर्भावस्था के परिणामों जैसे कि अपरिपक्व जन्म (PTB) और भ्रूण विकास प्रतिबंध (FGR) पर गहन मौलिक ज्ञान प्राप्त करना है

(ii) कुशल और टिकाऊ समाधानों की पहचान करने के लिए इस ज्ञान को लागू करें जो शमन में मदद करेंगे। संबंधित मृत्यु दर, तत्काल और दीर्घकालिक रुग्णता।

C. पार्टनर संस्थान

ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स

जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्रीय केंद्र

गुरुग्राम सिविल अस्पताल

सफदरजंग अस्पताल

D. लंबी अवधि में यह मंच अतिरिक्त शोध प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन के रूप में काम करेगा क्योंकि जन्म के आसपास नई परिकल्पनाएं उभरती हैं, गर्भावस्था के दौरान मातृ स्वास्थ्य और वयस्क रोग के भ्रूण की उत्पत्ति के आसपास के प्रश्न।



E.गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था की शुरुआत में और निश्चित रूप से गर्भावस्था के <20 सप्ताह से पहले नामांकित किया जाता है और जीसीएच में प्रसव तक अपनी देखभाल जारी रखने के लिए तैयार हैं।

(SOURCE - NEWS ON AIR)

7. मिशन 50K-EV4ECO

चर्चा में क्यों:- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने मिशन 50K-EV4ECO लॉन्च किया है, यह पहल स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए देश में 50,000 ईवी की खरीद को वित्त पोषित करेगी।



A. 'मिशन 50K-EV4ECO' का पायलट चरण प्रत्यक्ष (MSME) और अप्रत्यक्ष ऋण (NBFC) के माध्यम से दो, तीन और चार पहिया वाहनों के लिए विकास को गति देगा

B. यह योजना SIDBI-विश्व बैंक द्वारा विकसित योजना का अग्रदूत है

C. भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग विश्व स्तर पर पांचवें सबसे बड़े स्थान पर है और 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा बनने की उम्मीद है।

D. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) (1990 में आईडीबीआई बैंक की सहायक कंपनी के रूप में; वित्त मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय; मुख्यालय: लखनऊ) भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वित्त कंपनियों के समग्र लाइसेंसिंग और विनियमन के लिए शीर्ष नियामक निकाय है।

(SOURCE - INDIAN EXPRESS)



8. राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ)

चर्चा में क्यों:- केंद्र सरकार ने हाल ही में विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) के पूर्व प्रमुख को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।



A. भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, प्रधान मंत्री कार्यालय के तहत एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 2004 में देश की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (राँ) की तकनीकी शाखा के रूप में की गई थी।

B. प्रधानमंत्री कार्यालय के सीधे नियंत्रण में है और एक स्वायत्त संगठन के रूप में काम करता है।

C. प्राथमिक उद्देश्य: संचार संकेतों, इमेजरी इंटेलिजेंस और साइबर इंटेलिजेंस को इंटरसेप्ट करने और विश्लेषण करने सहित तकनीकी खुफिया एकत्र करें।

D. सूचना ब्यूरो और अनुसंधान और विश्लेषण विंग सहित देश की अन्य आसूचना एजेंसियों को भी तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

E. यह प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी के डेटाबेस को बनाए रखने और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए उन्नत उपकरण और तकनीक विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। एनटीआरओ का नेतृत्व एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है जो सीधे भारत के प्रधान मंत्री को रिपोर्ट करता है।

F. मुख्यालय नई दिल्ली में है, और देश के विभिन्न हिस्सों में इसके परिचालन केंद्र हैं।

(SOURCE - NEWS ON AIR)

